>

Title: Need to increase wages of workers in cooking mid-day meals in rural areas of the country, particularly, in Jalgaon Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने संबंधी सरकार की वचनबद्धता और विशेषकर ग्रामीण अंचलों में बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का अद्वितीय उदाहरण हैं, किंतु इस योजना में कुछ खामियां हैं। इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले आहार में जहां पौष्टिक तत्वों की कमी की शिकायतें आई हैं, वहीं आहार की गुणवत्ता के साथ समझौता करने की आवाजें भी उठती रहीं हैं। मैं इन्हीं कमियों के मुख्य बिन्दु के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश में छोटे एवं बड़े शहर हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान उन छोटे गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां बच्चे केवल भोजन के लिए ही स्कूल आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में बहुत सारे छोटे-छोटे गांव हैं, जिसमें औसतन 70 से 80 बच्चे एक स्कूल में आते हैं। परन्तु स्कूल में भोजन बनाने और बांटने के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है, उसका मानदेय अत्यंत थोड़ा होने के कारण भोजन की गुणवत्ता व नियमितता दोनों बेकार हो गई हैं। बच्चों को खाना नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो खाने लायक नहीं रहता है। क्योंकि जो भी खाना बनाता है, उसको उसका मेहनताना कम मिलने के कारण यह स्थिति आ गई है। इस भोजन तथा योजना का कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि कोई महिला खेतों में भी मजदूरी के लिए जाती है तो उसका कई गुना मजदूरी मिलती है। इसके चलते कोई भी महिला भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारी यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना अंत के कगार पर है।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसका मेहनताना बढ़ाकर 150 से 200 रूपये प्रतिदिन करना चाहिए जिससे हमारा शिक्षित भारत का सपना है, वह पूरा हो सके।